# राष्ट्रहित में है यूपी में किया गया निवेश : योगी

## मुख्यमंत्री ने उद्योग बंधु की बैठक में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों संग किया संवाद



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाल बहादुर शास्त्री भवन में उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक करते ●सूचना विभाग

- उद्योग समूहों से सीएसआर के जरिये प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान
- कहा, उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग बंधु को बनाया जाएगा और प्रभावी

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश केवल एक राज्य में नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किया गया है। आज उत्तर प्रदेश जिस आर्थिक मजबूती और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, उसमें उद्योग जगत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में उद्योग जगत सबसे बड़ा सहयोगी है। सरकार इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहती है। उन्होंने उद्योगपतियों से आह्वान किया कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड के माध्यम से प्रदेश के विकास में सहभागी बनें।

शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन में उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को केवल निवेशक नहीं, बल्कि विकास की साझेदारी का अभिन्न हिस्सा मानती है। प्रदेश में निवेश करने वाला हर उद्यमी सरकार को अपने साथ खड़ा पाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों से कहा कि अपनी रुचि और विशेषज्ञता के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास जैसे क्षेत्रों में सीएसआर फंड के तहत जरूर योगदान करें।

उद्योग बंधु की बैठकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर आयोजित उद्योग बंधु बैठकों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कहा कि उद्योग बंधु की राज्य स्तरीय बैठक केवल लखनऊ तक सीमित न रहे। प्रमुख सचिव आवास को निर्देश दिए कि आवासीय पार्किंग के लिए उपयोग हो रही भूमि पर अनावश्यक कर न लिए जाने की व्यवस्था लागू की जाए।

### 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभी तक हो चुकी चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है। जीबीसी-5 में छह लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश को डीरेगुलेशन 1.0 में देश में पहला स्थान मिला है।

### उद्योगपतियों ने रखा औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने बजट 2026-27 के संदर्भ में उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबार में सुगमता) को और प्रभावी बनाने के लिए उद्योगपतियों से सुझाव भी मांगे। सीआइआइ के उपाध्यक्ष अभिषेक सराफ ने रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिया। फिक्की के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड किए जाने की मांग रखी। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामलों में ओटीएस योजना लाए जाने की मांग भी उद्योगपतियों ने की। मुख्यमंत्री ने दलित इंडियन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मनीष वर्मा से कहा कि प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम से कम 10 युवा उद्यमियों को तैयार करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।

पूरी खबर पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें